



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़

राज्योत्सव



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव समापन समारोह

06 नवम्बर, 2024

राज्योत्सव स्थल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़



मुख्य अतिथि
श्री जगदीप धनखड़
माननीय उप राष्ट्रपति

अध्यक्ष
श्री रमेन डेका
माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़

अतिविशिष्ट अतिथि
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

अतिविशिष्ट अतिथि
डॉ. रमन सिंह
माननीय अध्यक्ष, विधानसभा, छत्तीसगढ़



विशिष्ट अतिथि
श्री अरूण साव
माननीय उप मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़
श्री रामविचार नेताम, माननीय मंत्री
श्री दयाल दास बदेल, माननीय मंत्री
श्री केदार कश्यप, माननीय मंत्री
श्री लखन लाल देवांगन, माननीय मंत्री
श्री श्याम बिहारी जायसवाल, माननीय मंत्री
श्री ओ.पी. चौधरी, माननीय मंत्री
श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, माननीय मंत्री
श्री टंकराम वर्मा, माननीय मंत्री
डॉ. चरणदास महंत, माननीय नेता प्रतिपक्ष
श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय संसद
श्री राजेश मण्ठ, माननीय विधायक
श्री पुरन्दर मिश्रा, माननीय विधायक
श्री मोती लाल साहू, माननीय विधायक
श्री अनुज शर्मा, माननीय विधायक
श्री गुरु खुशवंत साहेब, माननीय विधायक
श्री इंद्र कुमार साहू, माननीय विधायक



समस्त माननीय संसद, विधायक, मिश्र, मंडल, आयोग, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
एवं सदस्यगण, माननीय महापौर की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित है।

आप सादर आमंत्रित हैं...

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे



संपादकीय चंद्रबाबू नायडु का व्यापार और भाजपा की चुप्पी

टीबी की वापसी क्यों?

टीबी के मामले तेजी से बढ़े हैं। चौंकाने वाली बात है कि जब हमारे पास टीबी को रोकने, पहचानने और इलाज करने के साधन मौजूद हैं, तो भी इसके कारण इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं और लोग इसके शिकार बन रहे हैं। परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन नतीजा उलटा हो रहा है। यह कहानी कभी घातक बोमारी रह चुकी है और ट्यूबरकलोसिस (टीबी) की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की- ग्लोबल ट्यूबरकलोसिस रिपोर्ट 2024- वे मुताबिक 2023 में 82 लाख लोग टीबी से संक्रमित हुए, जो 1995 में निगरानी शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी संख्या है। यह आंकड़ा 2022 में सामने आए 75 लाख नए मामलों से काफ़ी अधिक है। इनके अलावा बड़ी संख्या की ऐसे लोगों के मौजूद होने का अनुमान है, जिनमें इस रोग का निदान नहीं हो पाया। अब डब्लूएचओ के महानिदेशक टेंड्रोस अधानोम गेब्रियासुस की इसकी टिप्पणी पर गौर कीजिए- चौंकाने वाली बात है कि जब हमारे पास टीबी को रोकने, पहचानने और इलाज करने के साधन मौजूद हैं तो भी इसके कारण इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं और लोग इसके शिकार बन रहे हैं। डब्लूएचओ ने अपनी रिपोर्ट जिक्र किया है विश्व दवा-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर/आरआर-टीबी) के मामलों में भी सुधार हुआ है। टीबी के सामान्य मामलों में इलाज की सफलता दर 88 फीसदी है, जबकि एमडीआर/आरआर-टीबी के मामलों में यह 68 फीसदी तक पहुंच गई है। फिर भी टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। टीबी की वापसी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत प्रमुख है। भारत सहित मध्यम आय वाले ज्यादातर देशों में यह स्थिति स्वास्थ्य के निरोधक (प्रीवेंटिव) पहलू पर जोर घटने वे कारण पैदा हुई है। हर सेवा के निजीकरण के दौर में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं रह गया है। डब्लूएचओ के मुताबिक लगभग 50 फीसदी मरीजों को इलाज के दौरान विनाशकारी खच का सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि उनका इलाज खಚ उनकी आय का 20 फीसदी से ज्यादा होता है। स्वाभाविक है विश्व रिपोर्ट में टीबी संबंधी सेवाओं के लिए फर्डिंग की कमी का खास उल्लेख किया गया है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र की उच्चस्तरीय बैठक में कहा गया था कि 2027 तक टीबी सेवाओं के लिए हर साल 22 बिलियन डॉलर जुटाए जाने चाहिए। 2023 में केवल 5.2 बिलियन डॉलर की फर्डिंग उपलब्ध थी- यानी कुल जरूरत का सिर्फ 26 फीसदी। ऐसे में टीबी की वापसी कोई हैरत की बात नहीं है।



इसमें प्रमुख सवाल यही है कि क्या दोनों मुख्यमंत्री दो से ज्यादा पैदा होने वाले बच्चों के पालन-पोषण का भार वहन करेंगे। क्या ऐसा करने वाले दंपत्ति को सरकार अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराएगी। जब तक सरकार ऐसी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होगी, तब तक तमाम बोझ कौन उठाएगा आंश्वप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने राज्य के लोगों से दो से अधिक बच्चे पैदा करने की मांग की है। सर्वाधिक आश्र्य यह है कि इन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इस मांग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साथ रखी है। मुसलमानों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर कोसने वाली भाजपा इन दो मुख्यमंत्रियों की मांग पर पूरी तरह मौन है। कारण साफ है कि चंद्रबाबू नायडु ने केंद्र की भाजपा सरकार को अपनी पार्टी तेलगुदेशम पार्टी के सांसदों का समर्थन दे रखा है। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र की मोदी सरकार नायडु की बैसाखियों पर टिकी है। इसलिए दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने के नायडु के बयान पर भाजपा ने मौन रखना ही बेहतर समझा। इसमें भाजपा को देश के लिए वैसा खतरा नजर नहीं आया, जैसा मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को लेकर दिखाई देता है। नायडु के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि लोगों को 16 बच्चे पैदा करने चाहिएं। यह बात उन्होंने सरकारी विवाह योजना के तहत 31 जोड़ों के विवाह समारोह में कही। स्टालिन का यह सुझाव नायडु द्वारा यह खुलासा किए जाने के एक दिन बाद आया है कि आंश्वप्रदेश में उनकी सरकार एक ऐसा कानून बनाने की योजना बना रही है, जिसके तहत केवल दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभागित करने की कवायद 2026 में होने वाली है। इससे लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 753 हो जाएगी। दक्षिण में क्षेत्रीय दलों को डर है कि इससे अधिक आबादी वाले राज्यों में सीटों की संख्या में भारी उछल आएगा, जबकि दक्षिण में यह वृद्धि मामूली होगी। इन दलों के नेताओं को लगता है कि पिछले कुछ दशकों में परिवार नियोजन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दक्षिणी राज्यों को दंडित किया जा रहा है, क्योंकि जिन

राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व अधिक होगा। वर्ष 2026 में क्षेत्र पुनर्विभाजन हो सकता है, इस अनुमान और उस समय की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि पुनर्विभाजन में जनसंख्या नियंत्रण के कदम उठाने वाले दक्षिणी राज्यों को भारी नुकसान होगा, जबकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं करने वाले हिंदी भाषी राज्य बड़ा फयदा उठाएंगे। उदाहरण के लिए, वर्तमान लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत है, जो विस्तारित लोकसभा में 48 प्रतिशत हो जाएगी। दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो जाएगी। बाकी राज्यों की हिस्सेदारी भी 34 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो जाएगी। आबादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई, तब देश की आबादी 36 करोड़ के आसपास थी। 1971 तक आबादी बढ़कर 55 करोड़ पहुंच गई। लिहाजा, सरकार ने 70 के दशक में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिणी राज्यों ने तो इसे अपनाया और आबादी काबू में की। मगर, उत्तर के राज्यों में ऐसा नहीं हुआ और आबादी तेजी से बढ़ती गई। ऐसे में उस समय भी दक्षिणी राज्यों की ओर से स्वाल उठाया गया कि उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग लागू करके आबादी कंट्रोल की और उनके यहां ही सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम होने का मतलब संसद में प्रतिनिधित्व कम होना। इसलिए विवाद हुआ। अभी तमिलनाडु की अनुमानित आबादी 7.70 करोड़ है और वहां लोकसभा की 39

सीटें हैं। जबकि, मध्य प्रदेश की आबादी 8.76 करोड़ है और यहां 29 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन होता है तो अभी की आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश में 87 लोकसभा सीटें हो जाएंगी और तमिलनाडु में 77 सीटें होंगी। सीटों की यह संख्या हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद वाले फॉर्मूले के हिसाब से है। इसी तरह केरल की अनुमानित आबादी 3.59 करोड़ है। अभी यहां 20 लोकसभा सीटें हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी 23.80 करोड़ है और यहां 80 सांसद हैं। अगर वही 10 लाख वाला फॉर्मूला लागू किया जाए तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 35 या 36 होगी। जबकि, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 235 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसी वजह से दक्षिणी राज्यों को आपत्ति है। उनका यही कहना है कि हमने आबादी नियंत्रित की, केंद्र की योजनाओं को लागू किया और उनके ही यहां लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु को हर हाल में आंध्रप्रदेश में अपने वोट बैंक को मजबूत रखना है। मुख्यमंत्री नायडु को इससे पर्क नहीं पड़ता कि भाजपा उनके बारे में क्या सोचती है। नायडु से समर्थन लेने की गरज भाजपा की है, नायडु की नहीं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नायडु ने आंध्रप्रदेश में जब मुस्लिमों को मिला आरक्षण नहीं हटाए जाने की घोषणा की, तब भी भाजपा से बोलते नहीं बन पड़ा। भाजपा को पता है कि नायडु से पंगा लेने का मतलब केंद्र सरकार का गिरना तय है। नायडु की पार्टी के 16 सांसदों का समर्थन केंद्र की भाजपा सरकार को हासिल है। इसलिए नायडु को

भाजपा और कद्र सरकार को परवाह नहीं है। नायडु ने लौकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान ही राज्य में मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने के अपने रुख को दोहराया दिया था। चंद्रबाबू नायडु ने कहा था कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और यह जारी रहेगा। टीटीपी प्रमुख का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना के जहीराबाद में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह धर्म के आधार पर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा मुसलमानों को नहीं दिए जाने देंगे। गैरतलब है कि इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल किए जाने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार के फैसले की निंदा की थी। मध्य प्रदेश की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया और कहा, एक बार पिछ कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से ओबीसी के साथ सभी मुस्लिम जातियों को शामिल करके कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है। इस कदम से ओबीसी समुदाय को आरक्षण के एक महत्वपूर्ण हिस्से से वंचित कर दिया गया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि कर्नाटक में यह आरक्षण पहली बार 1995 में एचडी देवेंगोड़ा की जनता दल सरकार द्वारा लागू किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रबाबू नायडु की पार्टी टीटीपी की तरह ही देवेंगोड़ा की जद (एस) अब भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सहयोगी है। भविष्य की राजनीति बचाने के लिए की जा रही। नायडु और स्टालिन की कवायद से सवाल भी खड़े होते हैं। इसमें प्रमुख सवाल यही है कि क्या दोनों मुख्यमंत्री दो से ज्यादा पैदा होने वाले बच्चों के पालन-पोषण का भार वहन करेंगे। क्या ऐसा करने वाले दंपत्ति को सरकार अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराएंगी। जब तक सरकार ऐसी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होगी, तब तक इनकी सलाह मानने वाले परिवारों को तमाम बोझ उठाना पड़ेगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दो से अधिक बच्चे होने पर जिम्मेदारी उठाने का जिक्र तक नहीं किया। इसी तरह भाजपा ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। तमिलनाडु के मामले में हो सकता है कि भाजपा जरूर कोई बयान देती।

आलेख आंखों के आगे इतिहास !

हां, आंखों देखा इतिहास ! ऐतिहासिक मोड़ पर है मौजूदा सिरमौर सभ्यता अमेरिका । वह इस सप्ताह अपने हाथों अपनी सभ्यता का इतिहास बनाएगी । अमेरिकी मतदाता तय करेंगे कि वे अपने सभ्यतागत मूल्यों और सांचे की निरंतरता में कमला हैरिस को जिताते हैं या वैयक्तिक तानाशाही जिद वाले डोनाल्ड ट्रंप को जिताते हैं । डोनाल्ड ट्रंप का अर्थ अमेरिका में विभाजन, संस्थाओं के पतन की गारंटी है । और जब कोई सभ्यता घर में विभाजित होती है तो उसकी ताकत, एकता, बुद्धि सब धरी रह जाती है । दो खेमों में विभाजित देश फिर धर्म, नस्ल, धन और अहंकार की आपसी लड़ाई का अखाड़ा होता है । ज्योंहि ऐसा हुआ त्योंहि सभ्यता को खत्म करने की ताक में बैठी बर्बर नस्ल और धर्म के लिए मौका खुलता है । आज इस मौके की ताक में चीन है तो पुतिन और इस्लाम भी है । इन तीनों के इरादे आंखों के आगे लाइव उपस्थित हैं । सोचें, जिस अमेरिका ने इस सदी के आरंभ में, 9/11 के बाद आतंकवाद (इस्लाम) के खिलाफ वैश्विक जंग का हुंकारा मारा था, वह भटका हुआ है और उसकी जगह वह इजराइल इस्लाम को ठोक रहा है, जिसके नेता नेतन्याहू बिना इस समझ के करुरता दर्शा रहे हैं कि वे बंधकों को छुड़वा रहे हैं, बदला ले रहे हैं, देश को सुरक्षित बना रहे हैं या कर्सेड है ? मेरा मानना है इजराइल का ठोकना इस्लाम को और जिद्दी बनाना है ? इसके नेतीजे उलटे और उग्र होंगे । उस नाते यहूदियों और ईसाईयों दोनों की नासमझी है जो वे अपने जिद्दी भाई (अब्राहम की संतान, इस्लाम) को अपने मूल धर्म में लौटाने, उनकी घर वापसी की नहीं सोचते, बल्कि ठोक-ठोक कर तीसरे महायुद्ध, सभ्यतागत संघर्ष का पानीपत मैदान बना दे रहे हैं । इस्लाम की लाइव ढुकाई के फोटो इस्लाम को सुलगाने वाले हैं । निश्चित ही अतीत में इस्लाम की करुर तलवार और कर्सेड के दृश्य आज के मुकाबले बेइंतहा खौफनाक थे । मगर पहले और दूसरे महायुद्ध के क्रम में यदि तीसरे महायुद्ध का सिनेरियो बन रहा है तो वह इस कारण पूरी पृथ्वी के लिए धातक होना है क्योंकि अब परमाणु हथियारों के जखिरे की

वास्तविकता भी है। इसलिए यहूदी बनाम मुसलमान, ईसाई बनाम इस्लाम, इजराइल बनाम ईरान, अमेरिका बनाम चीन, यूक्रेन बनाम रूस, उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया आदि की हकीकत का कुल सार आमने सामने की सीधी लड़ाई के पाले बनना है। हर पक्ष को जिद् खुखार होती हुई है। एक तरफ अमेरिका, पश्चिमी सभ्यता तथा ईसाई और यहूदी हैं तो दूसरी और चीन है। फिर इस्लाम (जो इजराइल की टुकाई से चीन-रूस से जुड़ता हुआ है) है। चीनी नेता बोलते नहीं हैं। न राष्ट्रपति माओ, देंग शियाओ पिंग भड़भड़िया नेता थे और न शी जिनफिंग हैं। ये चीनी नेता अतीत के अपने गौरव हान सभ्यता की वैश्विक पताका में चीन की श्रीवृद्धि के राष्ट्रवादी हैं। इनके लिए याकि मौजूदा चीनी कायमुनिस्ट पार्टी की ठोस पूँजी (रूसियों की तरह) करूर, कठोर, परिश्रमी चाहीने जनता है। जिसका कभी भी लोकतंत्र, मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता से सरोकार नहीं रहा है। तभी माओं की क्रांति हो या देंग और शी जिनफिंग के वैश्विक कारखाने, अमीरतम बनने का मिशन, सभी में नेतृत्व, पार्टी और जनता ने एकनिष्ठता से काम किया है। उसके लिए असुरी महाशक्ति बनना मुश्किल नहीं था। इसका लक्ष्य अब अमेरिका व पश्चिम सभ्यता की जगह अपने झंडे, अपनी व्यवस्थाओं में दुनिया को चलाना है। राष्ट्रपति शी जिनफिंग और उनके रणनीतिकारों ने चुपचाप बिसात बिछा दी है। चीन का लक्ष्य अमेरिका की जगह लेना है। एशिया का अधिपति होना है। चीन के लिए भारत, जापान, दक्षिण एशिया, ताइवान, आसियान देशों का जीरो अर्थ है। इसलिए क्योंकि ज्योंहिं अमेरिका का पतन हुआ, दुनिया की उसकी चौथराहट छूटी या उसने छोड़ी तो पलक झपकते ये तमाम छोड़े बढ़े देश चीन की कॉलोनी होंगे। यों भी दक्षिण या तीसरी दुनिया के ये देश आर्थिक तौर पर चीन से बंधे, उस पर आश्रित हैं। उधर परोक्ष तौर पर चीन ने रूस या पाकिस्तान के मार्फत मध्य एशिया के सभी इस्लामी देशों के अलावा अफगानिस्तान के तालिबान, ईरान और उन सब मुस्लिम देशों का विश्वास जीत लिया है जो इजराइल के हाथों घायल हैं। अपनी इस ग्रैंड योजना, वैश्विक बिसात में चीन किस शासितरता से फैसले करते हुए है इसका प्रमाण ब्रिक्स की हालिया शिखर बैठक थी। राष्ट्रपति शी जिनफिंग और पुतिन ने बैठक में तुर्की के उन राष्ट्रपति एर्दोंआन को बुलाया जो उड़गर मुसलमानों के उत्पीड़न के हवाले चीन के खिलाफ बोलते थे। एर्दोंआन को शी और पुतिन ने पटा लिया है।

ਪਾ

केंद्र सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन एक, जनवरी 2025 से प्रशासनिक सीमाएं सील हो जाएंगी और उससे पहले भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण का कार्यकाल अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि अगले साल जनगणना होगी। उसके अगले साल यारी 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और फिर इसी आधार पर 2029 में साथ होने वाले चुनाव में एक तिहाई सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में, जहां 16 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाना था, वहां कहा कि 'जब हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां संसद में सीटों की संख्या कम होने वाली है तो हमें छोटा परिवार क्यों रखना चाहिए?' इसके आगे उन्होंने नवविवाहित जोड़ों से ज्यादा बच्चे पैदा करने और उन्हें सुंदर तमिल नाम देने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने संसद में सीटों की संख्या कम होने के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा लेकिन उनका इशारा परिसीमन के बाद की स्थितियों की ओर था। उनसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आग्रह किया था। हालांकि उनका घोषित सरोकार

यह था कि दक्षिण के राज्यों में आबादी बढ़ी हो रही है और कामकाजी युवाओं की संख्या कम हो रही है। परंतु कहीं न कहीं वे भी इस बात से चित्तित हैं कि अगर आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ तो दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक हैसियत घटेगी। तभी यह बड़ा सवाल है कि लोकसभा सीटों के परिसीमन का आधार क्या होगा? क्या सीधे तौर पर जनसंख्या के हिसाब से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों को फायदा होगा और दक्षिण भारत के राज्य घाटे में रहेंगे। तभी चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन की चिंता सामाजिक या अर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दिखती है। यह चिंता क्षेत्रीय वर्चस्व और फिर अस्मिता की राजनीति में भी बदल सकती है, जिससे एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार को परिसीमन के फॉर्मूले के बारे में तर्कसंगत तरीके से विचार करना होगा और उस पर सभी दलों व राज्यों की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। ध्यान रहे लोकसभा सीटों का परिसीमन जम्मू कश्मीर की तरह नहीं होगा, जहां मनमाने तरीके से भौगोलिक सीमाओं का ध्यान रखे बगैर इस तरह से विधानसभा सीटों का सीमांकन हुआ कि जम्मू क्षेत्र में छह सीट बढ़ गईं और कश्मीर घाटी में सिर्फ एक सीट बढ़ी। आजादी के बाद से मोटे तौर पर आबादी के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या तय

होती रही है। तभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तमिलनाडु में 39 हैं। लेकिन आजादी के बाद राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अलग अलग तरीके से लागू किया। आर्थिक रूप से विकसित राज्यों ने बेहतर ढंग से जनसंख्या नियंत्रण का किया तो उनके यहां जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे आ गई। दक्षिण के राज्यों में तो जनसंख्या बढ़ने की दर रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। इसका मतलब होता है कि अगर दो लोग मिल कर 2.1 बच्चे पैदा करते हैं तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी वह स्थिर हो जाएगी। दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की दर 1.6 फीसदी है, जो रिप्लेसमेंट रेट से काफी कम है, जबकि उत्तर के राज्यों खास कर बिहार और उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थिति रही है तभी दक्षिण के राज्यों में आबादी नियंत्रित हो गई और उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ती चली गई। हालांकि अब वहां भी रफ्तार धीमी हो रही है लेकिन उन राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर इस आधार पर उनकी लोकसभा सीटें बढ़ती हैं तो यह उन राज्यों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने अपने यहां आबादी का बढ़ा रोका। उन्होंने अच्छा काम किया इसके लिए उनको सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर सरकार पारंपरिक रूप से आबादी को आधार बनाती है और औसतन 20 लाख की आबादी पर एक सीट का फॉर्मूला तय होता है तो दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा,

जबकि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 से बढ़ कर 120 हो जाएगी। बिहार में 40 से बढ़ कर 70 हो जाएगी। सोचें, इसमें इन राज्यों की राजनीतिक हैसियत कितनी बढ़ जाएगी? अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल लोकसभा की सीटों में बड़ी बढ़ोतरी करनी होगी। वैसे नए संसद भवन में इसकी तैयारी पहले हो चुकी है। नए संसद भवन में निचले सदन यानी लोकसभा में 880 सासदों के बैठने की व्यवस्था है। अगर संख्या इतनी नहीं भी बढ़ाएं तब भी आठ सौ तक संख्या जा सकती है। इस फॉर्मूले से यानी आबादी के अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला होता है तो दक्षिण के सभी राज्यों को मिला कर करीब 20 सीट का फायदा होगा। लेकिन उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में डेढ़ सौ से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। अगर सरकार लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाने का फैसला करती है तब परिसीमन में जनसंख्या का पैमाना 30 लाख की आबादी पर एक सीट का रखना होगा। अगर ऐसा किया जाता है तब उत्तर प्रदेश में 80 और बिहार में 42 सीटें होंगी। लेकिन ऐसे में कम से कम आठ राज्य ऐसे होंगे, जहां लोकसभा की एक भी सीट नहीं बनेगी क्योंकि उन राज्यों की आबादी 30 लाख से कम है। अगर किसी भी राज्य में जीरो सीट नहीं रखनी है यानी चाहे जितनी आबादी हो उसे कम से कम एक लोकसभा सीट देनी है तो सबसे छोटे राज्य की आबादी के हिसाब से एक सीट का फॉर्मूला बनाना होगा। ऐसे में ओवरऑल सीटों की संख्या में छह सीटों की बढ़ोतरी होगी यानी कुल सीट संख्या 549 हो जाएगी।

परिस्थिति का क्या पैमाना होगा ?

—fin—

मौजूदा दौर में जम्मू-कश्मीर राज्य के सियासी रहनुमां जशन-ए-जम्हूरिया मना रहे हैं, मगर 1947-48 के युद्ध में कश्मीर के मुहाफिज शेर जंग थापा, कमान सिंह पठानिया, अनन्त सिंह पठानिया, ठाकुर पृथी चंद्र व खुशाल ठाकुर की शूखरता पर गुमनामी का तमस छा चुका है वाईस अक्टूबर 1947 को पाक सेना ने हजारों कबायली लड़ाकों के साथ जम्मू-कश्मीर रियासत पर हमला कर दिया था। जम्मू-कश्मीर के शासक 'हरि सिंह' के लिए परिस्थितियां गंभीर हो चुकी थीं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर रियासत का भारत में इलाहाक हुआ तो रियासत की स्टेट फोर्सेज भिरघात का शिकार हो गई। गिलगित व बलोचिस्तान की सुरक्षा में तैनात जम्मू-कश्मीर राज्य की फोर्स 'गिलगित स्काउट' तथा सैकड़ों मुस्लिम सैनिक विद्रोह करके पाक सेना से जा मिले थे। गिलगित स्काउट के कमांडर मेजर 'विलियम ए ब्राउन' ने गिलगित के गवर्नर ब्रिगेडियर 'धनसारा सिंह' को कैद करके एक नवंबर 1947 को अपने मुख्यालय पर पाकिस्तान का परचम फहरा दिया था। गिलगित एजेंसी की सीमा पर 'बुंजी' में तैनात 'जम्मू कश्मीर इन्फैट्री' की 'छठी'

के कर्नल 'अब्दुल मजीद खान' नद कर लिया गया था। उसी के कैटन 'मिर्जा हसन खान' ने स्लेम सैनिकों के साथ मिलकर अंजाम देकर बुंजी के निकट में तैनात अपनी ही सिख कंपनी करके कई सिखों को हलाक कर पाक सेना से जा मिले थे। उसी कश्मीर इन्हैंट्री में सेवारत के 'शेर जंग थापा' उस समय कंपनी के साथ लद्दाख सेक्टर पर। शेर जंग थापा को कर्नल पद त त करके स्कर्फू में अपनी की कमान संभालने का आदेश लाख से स्कर्फू तक का सफर पैदल शेर जंग तीन दिसंबर 1947 को। शेर जंग ने कैटन कृष्ण सिंह में सिख सैनिकों को 'त्सारी' तथा 'सिंह' के नेतृत्व में एक सैन्य 'गिरि' में तैनात किया। मात्र साठ साथ शेर जंग ने स्कर्फू में मार्चा दस परवारी 1948 को कैटन दो कंपनियों के साथ शेर जंग का लिए स्कर्फू पहुंचे, मगर शेर यालियन के कैटन 'नेक आलम' मुस्लिम सैनिकों के साथ पाक मिलकर दस परवारी 1948 को सारी में तैनात सिख कंपनी पर



हमला करके कैप्टन कृष्ण सिंह सहित लगभग पूरी कंपनी को हलाक करके पाक सेना में शामिल हो गया। 12 फरवरी 1948 को पाक फैज ने स्कर्ट्डू किले की धेराबंदी करके हमले शुरू कर दिए। शेर जंग के नेतृत्व में सैनिक पाक फैज के हमलों को नाकाम करते रहे, लेकिन पाक फैज की उस बढ़े पैमाने की धेराबंदी के बाद शेर जंग को सैन्य सहायता नसीब नहीं हुई थी। जम्मू-कश्मीर राज्य बलों से बगावत करके पाक सेना से जा मिले कर्नल बुरहानुदीन, मोहम्मद खान व बाबर खान गिलगित स्क्वाउट की कमान संभाल कर स्कर्ट्डू किले को धेर चुके थे। शेर जंग की बटालियन के भागोड़े कर्नल 'एहसान अली' की क्यादत में 'आईबेक्स फर्स' तथा चित्राल रियासत



छठ पर्व, एकादशी एवं प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

लोक आस्था एवं सूर्योण्डनता के महापर्व

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

धर्मेन्द्र सिंह "DK"
संचालक
मनोकर कांडेत कामेटी सूरजपुर

प्रियंका सिंह
पार्षद - लाई क. 13
नगर पालक परिषद बिश्रामपुर

दीपावली, छठ एवं एकादशी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

मंगल सिंह यादव

प्रदेश समन्वयक : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
पिछड़ा वर्ग एवं प्रभारी जिला सूरजपुर
कार्यवाहक अध्यक्ष : बैकवर्ड वलास ओबीसी कॉल
इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर जोन

दीपावली, छठ एवं एकादशी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

विनोद जिंदल

युवा उघोगपति

मन रोड बिश्रामपुर, जिला सूरजपुर (छा.)

दीपावली, छठ एवं एकादशी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

सुजीत सिंह

अध्यक्ष, क्षतिय समाज बिश्रामपुर

शुभेच्छु : डॉ. बी एन सिंह, विकास सिंह

विनीत : क्षत्रिय समाज बिश्रामपुर

दीपावली, छठ एवं एकादशी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

हुकुम वंद राजवाडे
संस्थापक

चलता राजवाडे
संचालक

भरत राजवाडे
संचालक

मन रोड बिश्रामपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

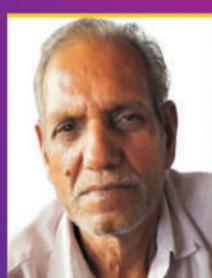
राजपाड़े
मेटल एटोर्स

हमारे यहां समस्त धरेलु बर्तनों, पूजा में धातु सामग्रीयों एवं धातुओं के मूर्तियों का अथाह संग्रह उपलब्ध

छठ पर्व, एकादशी एवं प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रयाम आंलो पार्ट्स

नोट - दो पहिए वाहनों का प्रत्येक पार्ट्स सही कीमत पर
विक्री का एक मात्र केंद्र, शहर का जाना पहचाना एक नाम



संस्थापक
प्रकाश
सिंहल



संचालक
महेश
सिंहल
पिंटू



शिवम
सिंहल

मन रोड बिश्रामपुर - सूरजपुर छत्तीसगढ़

दीपावली, छठ एवं एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं

धर्मेन्द्र सिंह
युवा नेता

नगर पंचायत
बिश्रामपुर (छ.ग.)

प्रियंका सिंह
पार्षद

दीपावली, छठ एवं एकादशी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

महालक्ष्मी स्मॉल पैथोलैब

नोट :- हर प्रकार की स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं

विनित कुमार श्रीवास्तव
संचालक

गल्फ बायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने,
मन रोड बिश्रामपुर



छठ पर्व, एकादशी एवं प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

छठ पर्व, एकादशी एवं प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

आत्मीय स्वजन, 46 वर्षों की गौरवशाली व्यवसायिक यात्रा में परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद, आपके स्नेह एवं आत्मीयता ने हमें निरंतर आगे बढ़ने का संबल प्रदान किया है विश्वास और संबंधों की इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हम कृत संकल्पित हैं।

हमारे प्रतिष्ठान

जलतरंग स्वीट्स

मेन रोड विश्वामपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(का) नयी साज सज्जा के साथ

भव्य शुभारंभ

में आप सप्तरिवार सादर आमंत्रित हैं...
पधारियेगा जरूर...



मिठाईयां

बेकरी

झायफूट

नमकीन

सह-संस्थान

साहिब ट्रेडर्स

Mob. 8871310000, 7000304812

विनित :
इन्द्रजीत सिंह मखीजा
गुरुविन्दर सिंह मखीजा
प्रितपाल सिंह मखीजा

**संस्थापक - इंद्रजीत
सिंह मखीजा**

छठ पर्व, एकादशी एवं प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

होंडा शोरूम

प्रत्येक कंपनियों की सेकंड हैंड ट्रूलीलर गाड़ियां हर रेंज में उपलब्ध



राजेन्द्र थाकुर गुड्डू



राजकुमार थाकुर पिंडू



अतुल थाकुर



ओम थाकुर



अंश थाकुर



अक्षय थाकुर

धनश्री होटल के सामने, मेन रोड विश्वामपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

मो. नं. 9826618390, 9926846650

www.dainikvishwapariwar.com

मेन रोड विश्वामपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

www.dainikvishwapariwar.com

छठ पर्व, एकादशी एवं प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

JAI BALAJI MOTORS AND LUBRICANTS

All Company Genuine Spear Partes Available

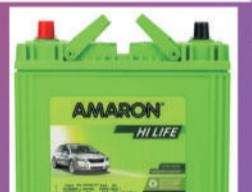
ARVIND MITTAL
MOB : 9826025476
EMAIL ID . -
jaibalajimotorsbspr@gmail.com



JAI BALAJI TYRES AND BATTERY JAI BABAJI PUC CENTER



GOURAV KUMAR MITAL
MOB : 9826125476
EMAIL ID . -
jaibalajityrebspr@gmail.com

# ALL COMPANY
TYRE AND
BATTERY
@ AVAIALBLENEAR AMBEDKAR CHOWK MAIN ROAD,
BISHRAMPUR, DIST - SARGUJA (C.G.) 497226

छठ पर्व, एकादशी एवं प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

आशा जपेलर्स



मुकेश सोनी

हीरा, सोना, चांदी, आभूषणों रुद्राक्ष एवं सभी रलों का एक मात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान

मेन रोड विश्वामपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

www.dainikvishwapariwar.com